



## ग्रामीण आर्थिक विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका

**Ragini Agrawal, Ph. D.**

*Associate Professor, Department of Economic, K R Girls (P.G.) College, Mathura, U.P.*

### Abstract

सामाजिक-आर्थिक विषमता प्रत्येक समाज की ऐसी जीती जागती सच्चाई तथा वास्तविकता है जो मानव जीवन के आरम्भ से ही पायी जाती रही है। वर्तमान में भारत जैसे कृषि प्रधान देश में आर्थिक विषमता और भी अधिक विकराल रूप में विद्यमान है। आर्थिक विषमता की बढ़ती समस्या, जिसकी जड़ बेरोजगारी की समस्या है; हमारे सामाजिक-आर्थिक विकास में बाधक एवं राष्ट्रीय समस्याओं की जनक है। यही कारण है कि सामाजिक-आर्थिक विकास की समस्या के समाधान के लिए स्वातंत्र्योत्तर भारत में विकास योजना के माध्यम से सतत् प्रयास किये जाते रहे हैं किन्तु समस्या जस की तस है। ऐसी स्थिति में राज्य का परम दायित्व है कि वह अपने समाज तथा क्षेत्रीय समुदायों के अन्दर आर्थिक तंगी के शिकार लोगों की बेहतरी के लिए विभिन्न व्यवस्थित ग्रामीण विकास योजनाओं का निर्माण तथा क्रियान्वयन करे। भारत सरकार ने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कृषि, कृषिकों तथा निर्बल वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप भारतीय समाज के आर्थिक ढाँचे को चिन्तन में रखकर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापनायें करके मुख्य रूप से निर्बल वर्गों तथा अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास हेतु उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुदानित वित्त ऋण रूप में किस्तों के रूप में प्रदान करके अतिरिक्त आय तथा रोजगारों के अतिरिक्त संसाधन सृजित करने का कार्य प्रारम्भ किया है। पूर्व में हुए आनुभविक अध्ययनों से स्पष्ट है कि (1) रोजगारों के नए-नए साधन सृजित हुए हैं (2) रोजगारों के दैनिक आय वाले संसाधन सृजित हो जाने से कार्य दिवसों की संख्या बढ़ी है जिससे बेरोजगारी की समस्या में कमी आयी है।

**तकनीकी शब्दावली:** क्षेत्रीय बैंक, वित्तीयन प्रणाली, ग्रामीण विकास, निर्बल वर्ग।

### परिकल्पनायें:

- परिकल्पना (1) : कि क्षेत्रीय बैंकों की वित्तीयन प्रणाली सहज तथा सरल है ।
- परिकल्पना (2) : कि ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत कृषकों को ऋण प्रदान करने में क्षेत्रीय बैंकों सहायक हैं।
- परिकल्पना (3) : निर्बल वर्गों तथा ग्रामीण विकास में क्षेत्रीय बैंकों अहम भूमिका का निर्वाह कर रही हैं
- परिकल्पना (4) : कृषकों की सुधरी सामाजिक-आर्थिक दशाएं क्षेत्रीय बैंकों के योगदान की परिचायक है।

**शोध प्रविधि:** अध्ययन विषय की प्रकृति तथा उद्देश्यों को देखते हुए "साक्षात्कार-अनुसूची" को प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु अपनाया है। यथार्थ अनुबोध के लिए, असहभागी किन्तु प्रत्यक्ष "अवलोकन" प्रविधि का सहारा भी लिया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में "आगमनात्मक पद्धति" को अपनाते हुए सामान्यीकृत निष्कर्ष निकाले गए हैं। निष्कर्षों की प्रस्तुतिकरण परिकल्पनाओं की सार्थकता तथा

सत्यता की जाँच के उपरान्त अनुभवगम्य तरीके से किया गया है। निदर्शितों के रूप में, जनपद मथुरा के ग्रामीण अंचल के कृषकों का चयन किया गया है।

### **विवेचना एवं परिलब्धियाँ:**

कुल 100 सर्वेक्षितों में से 97.00 प्रतिशत सूचनादाताओं ने प्रथम दृष्टया यह स्वीकार किया है कि कृषि तथा कृषिकों पर क्षेत्रांतर्गत बैंकों का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है; सम्प्रति कृषि, कृषिक एवं कृषि उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है क्योंकि रोजगार मिलने के दिवसों की संख्या में वृद्धि हुई है। योजनान्तर्गत लाभान्वित होने से व्यवसाय भी प्रत्यक्षतः प्रभावित हुए हैं। सूचनादाताओं ने बताया है कि रोजगारों के अतिरिक्त साधन सृजित हो जाने से जो व्यवसाय/रोजगार के संसाधन उन्होंने अर्जित किए हैं; जो कि दैनिक आय की दृष्टि से बेहतर हैं। जिससे उनके परिवारों के जीवन स्तरों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उनके आवास तथा आवासीय दशाएं काफी सुधरी हैं; झोंपडियाँ तथा कच्चे आवास पक्के हुए हैं, दुधारू भैंस मिल जाने से खानपान में भी सुधार हुआ है। रोजगारों के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हो जाने से बन्धुआ मजदूरी कम हुई है यहाँ तक कि सामयिक मजदूरों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसे भी निर्बल वर्गीय परिवारों पर पड़ने वाला सकारात्मक प्रभाव ही माना जायेगा। सूचनादाताओं के परिवारों में शैक्षिक वातावरण तथा स्तरों का सूक्ष्म अध्ययन करने पर विदित हुआ है कि लाभान्वित होने से पूर्व की अपेक्षा लाभान्वित होने के पश्चात बच्चों की शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा है जो कि शैक्षिक प्रगति का प्रतीक है। इस रूप में भी यह कहा जा सकता है कि निर्बल वर्गों के शैक्षिक विकास में क्षेत्रांतर्गत बैंकों की भूमिका सकारात्मक है। सामाजिक जातिगत तथा आर्थिक श्रेणियों (लघु किसान, सीमान्त किसान, ग्रामीण दस्तकार, भूमिहीन श्रमिक) के निदर्शित परिवारों का सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन करने पर विदित हुआ है कि अनुसूचित जातियों में गरीबी की रेखा को पार करने वाले परिवारों का प्रतिशत 87.00 प्रतिशत (सर्वाधिक), पिछड़ी जातियों में 86 प्रतिशत तथा सवर्ण जातियों में 87.00 प्रतिशत पाया गया है लेकिन औसतन रूप से 86.00 प्रतिशत निर्बल परिवार गरीबी की रेखा को पार करने में सफल हुए हैं। अनुसंधित्सु ने सामाजिक आधार पर निदर्शित परिवारों के दैनिक शुद्ध लाभ (प्रति परिवार तथा प्रति व्यक्ति) भी ज्ञात किए हैं तो सवर्ण, पिछड़ी तथा अनुसूचित जातियों के लाभान्वितों प्रति परिवार शुद्ध लाभ क्रमशः 7.27 रु०, 13.35 रु० तथा 26.40 रु० तथा प्रति व्यक्ति क्रमशः 1.37, 2.89 तथा 6.26 रुपए शुद्ध लाभ मिलना; परिकलन किया गया है। योजनान्तर्गत लाभान्वित होने से परिवारों को मिलने वाला शुद्ध लाभ औसतन 15.67 रु० प्रति परिवार/दिन तथा 3.33 रु० प्रति व्यक्ति/दिन पाया गया है। क्षेत्रांतर्गत बैंकों से ऋण लेने के प्रसंग में निदर्शितों की अभिवृत्तियों का भी अध्ययन किया गया तो ऋण लेने से पूर्व 65.00 प्रतिशत निदर्शित पक्षधर थे लेकिन विकास योजनान्तर्गत लाभान्वित होने के पश्चात 92 प्रतिशत निदर्शित पक्षधर पाए गए हैं जो (+) 36.67 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है; इन प्राथमिक तथ्यों से सुस्पष्ट है कि अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास में मथुरा जिले की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिकाएं अहम तथा रचनात्मक हैं।

प्राथमिक तथ्यों द्वारा प्राप्त तालिकाओं के अन्तर्गत आंकड़ों के विश्लेषण तथा सम्बन्धित विवेचन से विदित होता है कि—

- (1) क्षे. ग्रामीण बैंकों से प्राप्त अनुदानित ऋणों से कृषि के सन्दर्भ में भू-विन्यास प्रभावित हुआ है तथा कृषि की दशाएं सुधरी हैं।
- (2) क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप क्षे.ग्रा. बैंकों की स्थापनाओं से कृषिकों को जरूरतों के अनुसार अनुदानित ऋण किस्तों पर मिल जाने से, परम्परागत खेती न रहकर; कृषि तकनीक विकसित हुई है।
- (3) क्षे.ग्रा. बैंकों से लाभान्वित होने से रोजगारों के अतिरिक्त साधन सृजित हुए हैं जिससे प्रति परिवार तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है।
- (4) क्षे.ग्रा. बैंकों से वित्त पोषण के कारण रोजगारों के अतिरिक्त साधन सृजित हो जाने से लाभान्वितों के रोजगारों में वृद्धि तथा कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि हुई है ऐसा होने से उनकी आय बढ़ी है।
- (5) अन्य व्यावसायिक तथा सहकारी बैंकों की तुलना में क्षे.ग्रा. बैंकों की वित्तीय प्रणाली विभिन्न सीमाएं होते हुए भी सरल व सहज है।
- (6) क्षे.ग्रा. बैंकें ग्रामीण बेरोजगारी तथा निर्धनता उन्मूलन में सहायक हैं।
- (7) क्षे.ग्रा. बैंकों ने विभिन्न ग्रामीण विकास योजनान्तर्गत अनुदानित ऋण किस्तों पर प्रदान करके निर्बल वर्गों में ग्रामीण विकास के प्रति जन जागरूकता जनित की है।
- (8) अध्ययन किए गए 76 प्रतिशत सूचनादाताओं का मानना है कि इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने "स्वयं सहायता समूहों" की स्थापनाएं करके निर्बल वर्गों को साहूकारी प्रथा से मुक्ति प्रदान की है।
- (9) 77.00 प्रतिशत सूचनादाताओं ने यह स्वीकारोक्तियां की हैं कि ग्रामीण निर्बल वर्गों के विकास में क्षे.ग्रा. बैंकें वित्तीय सहायताएं प्रदान करके अहम तथा सकारात्मक भूमिकाएं निर्वाह कर रही हैं।
- (10) 94 प्रतिशत लाभान्वितों ने स्वीकार किया है कि दैनिक आय वाले रोजगारों (जो कि तृतीय क्षेत्र की सेवान्तर्गत आते हैं) की संख्या में काफी अधिक वृद्धि हुई है।

प्राप्त निरीक्षणों एवं शोधपरक निष्कर्षों के प्रकाश में यह सुस्पष्ट है कि ग्रामीण अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिकाएं सकारात्मक एवं पूर्णतः विकासोन्मुखी हैं।

**प्राथमिक तथ्यों का सारणीयन**

**तालिका नं.1 : सूचनादाताओं के अनुसार कृषि तथा कृषिकों पर क्षे.ग्रा. बैंकों का प्रभाव**

क्रमांक	कृषि तथा कृषिकों पर प्रभाव की प्रकृति	सूचनादाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	सकारात्मक	97.00	97.00
2.	नकारात्मक	00	00.00
3.	कोई प्रभाव नहीं	03	03.00
4.	अनुत्तरित	—	00.00
	समस्त योग	100	100.00

**तालिका नं. 2 : क्षे.ग्रा. बैंकों से ऋण लेने के बारे में निदर्शितों के अभिमत / दृष्टिकोण**

क्रमांक	अभिमतों का विवरण	ऋण लेने से पूर्व	ऋण लेने के पश्चात्
1.	पक्ष में	65	65.00
2.	विपक्ष में	35	35.00
	समस्त योग	100	100.00

**तालिका नं. 3 : "क्या क्षे.ग्रा. बैंकों से निर्बल वर्गीय परिवारों पर कोई प्रभाव पड़ा है?"**

**प्रश्न का प्रत्युत्तर**

क्रमांक	प्रश्न का प्रत्युत्तर	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1.	निर्बल वर्गीय परिवारों कह सामाजिक- आर्थिक दशाएं सुधरी हैं।	92.	92.00
2.	निर्बल वर्गीय परिवारों की सामाजिक- आर्थिक दशाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।	—	00.00
3.	उदासीन उत्तर प्रदान करने वाले उत्तरदाता	08	08.00
4.	अनुत्तरित रहे	—	00.00
	समस्त योग	750	100.00

**संदर्भ:**

अल्फ्रेड, जे.के. ; (2010) द डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च, द यूनिवर्सिटी आफ शिकागो प्रेस, शिकागो।

बाइरेस, टी.जे. ; (2007) द स्टेट, डबलपमेन्ट प्लानिंग एण्ड लिबरलाइजेशन इन इण्डिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।

वर्धन, पी.के. ; (2009) द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डबलपमेन्ट इन इण्डिया; ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।

- बाबा, एस.आर. ; (1997) स्ट्रक्चरल चेन्जिंग इन इण्डियन इकोनॉमी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी प्रेस, (पंजाब) अमृतसर।
- बाजपेयी मधुरिमा ; (2007) इन्दौर उज्जैन सम्भाग में सोयाबीन उद्योग, प्रकाशित शोध ग्रन्थ, रिसर्च पब्लिकेशन (राज.) जयपुर।
- भल्ला, एन.के. ; (2001) योजना आयोग, केन्द्र शासन (मैनुअल), दिल्ली।
- बोगम पी.आर. एण्ड (2012) द कालेज ऑफ ग्रेजुएट - अन बुडहाल एम. ; ऐम्प्लायमेंट इन इण्डिया, मैक मिलन एण्ड कम्पनी, लन्दन।
- चेलियाह, राजा.जे. ; (2011) इनकम, पॉवर्टी एण्ड बियोन्ड: ह्यूमन डबलपमेन्ट इन इण्डिया, 'सोसल साइन्स' प्रेस, नई दिल्ली।